Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-5(A)| May-2026

Original Article

गिग अर्थव्यवस्था: अवसर, चुनौतियाँ एवं भावी संभावनाएँ

डॉ. सुरेखा पिपलानी
प्रोफेसर (अर्थशास्त्र विभाग), जी. यू. (पी. जी.) कॉलेज, बहेड़ी (बरेली), एम. जे. पी. रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
E-mail: piplanisurekha03@gmail.com

Manuscript ID:
JRD -2026-180506
ISSN: 2230-9578
Volume 18
Issue 5(A)
Pp. 23-26
May- 2026
Submitted: 15 Apr. 2026
Revised: 25 Apr. 2026
Accepted: 10 May. 2026
Published: 31 May 2026

सारांश:

गिग अर्थव्यवस्था आधुनिक श्रम बाजार की एक नयी और तेजी से उभरती हुई अवधारणा है। सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तार, इंटरनेट और स्मार्टफोन की सुलभता ने पारम्परिक रोजगार के प्रतिमानों को बदल दिया है। गिग कार्यबल, जो मुख्य रूप से डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित होता है, आज वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग बन चुका है। यह मॉडल एक ओर युवाओं को रोजगार में लचीलापन और तात्कालिक आय के अवसर प्रदान करता है, वहीं दूसरी ओर यह श्रम अधिकारों, सामाजिक सुरक्षा तथा आय की अनिश्चितता से जुड़ी गंभीर चुनौतियाँ भी उत्पन्न करता है। प्रस्तुत अध्ययन गिग अर्थव्यवस्था की प्रकृति, इसके सामाजिक एवं आर्थिक प्रभावों, श्रमिकों की चुनौतियों, कानूनी एवं नीतिगत ढाँचे की आवश्यकता तथा भावी संभावनाओं पर प्रकाश डालने का प्रयास करता है। शोध का निष्कर्ष यह है कि गिग अर्थव्यवस्था रोजगार सृजन का एक अच्छा माध्यम है, लेकिन श्रमिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह अभी भी एक चिंतन का विषय है।

मुख्य शब्द: *गिग अर्थव्यवस्था, डिजिटल प्लेटफॉर्म, श्रम बाजार, सामाजिक सुरक्षा, नीतिगत ढाँचा*

प्रस्तावना:

वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी तथा इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के कारण श्रम बाजार की संरचना में व्यापक परिवर्तन हुआ है। इस परिवर्तन का सबसे स्पष्ट उदाहरण गिग अर्थव्यवस्था का उदय है। यह एक ऐसी मुक्त बाजार व्यवस्था है जहाँ स्वतंत्र श्रमिक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अल्पकालिक अनुबन्धों पर काम करते हैं। पारम्परिक स्थायी नौकरियों के स्थान पर लचीले, अल्पकालिक और परियोजना-आधारित कार्य मॉडल तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। इसके लिए उन्हें कार्य के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) गिग श्रमिकों को उन श्रमिकों के रूप में परिभाषित करता है जो डिजिटल माध्यम से अल्पकालिक कार्य प्राप्त कर उन्हें पूर्ण करते हैं। कोविड महामारी ने इस प्रवृत्ति को और अधिक बढ़ावा दिया। लॉकडाउन के कारण जब पारम्परिक रोजगार समाप्त हो रहे थे, तब डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से काम करने वाले गिग कर्मियों ने इस प्रकार की नवीन संभावनाएँ खोजीं। नीति आयोग 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 77 लाख श्रमिक गिग अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए थे तथा 2029-30 तक इनकी संख्या बढ़कर 2.35 करोड़ होने की संभावना है।

Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0)
This is an open access journal, and articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Public License, which allows others to remix, tweak, and build upon the work noncommercially, as long as appropriate credit is given and the new creations ae licensed under the idential terms.

Address for correspondence:
डॉ. सुरेखा पिपलानी प्रोफेसर (अर्थशास्त्र विभाग), जी. यू. (पी. जी.) कॉलेज, बहेड़ी (बरेली) एम. जे. पी. रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

How to cite this article:
पिपलानी, सुरेखा. (2026). गिग अर्थव्यवस्था: अवसर, चुनौतियाँ एवं भावी संभावनाएँ. Journal of research & development, 18(5(A)), 23–26. https://doi.org/10.5281/zenodo.20918445

Quick Response Code:
Website: https://jrdrvb.org/
DOI: 10.5281/zenodo.20918445
OPEN ACCESS

Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-5(A)| May-2026

गिग अर्थव्यवस्था की पृष्ठभूमि एवं तकनीकी आधार:

भारत में 2016 के बाद आयी डिजिटल क्रांति, इंटरनेट तक बढ़ती पहुँच, डिजिटल भुगतान प्रणालियों, स्मार्टफोन के प्रसार तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म के विस्तार ने गिग अर्थव्यवस्था के विकास का मार्ग सुगम कर दिया है। आज रिक्शा चालक से लेकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर तक ऐप के माध्यम से कार्य ढूँढने में सक्षम हैं। डिजिटल भुगतान (UPI) के सरलीकरण ने इस क्षेत्र के विस्तार को अप्रतिम गति प्रदान की है। भारतीय शहरों में मध्यवर्ग की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ी है। मध्यम वर्ग के जीवन में समय की कमी और सुविधाओं की बढ़ती माँग ने ऑन-डिमांड सेवाओं की आवश्यकता को जन्म दिया है। उपभोक्ता अब ऐप प्लेटफॉर्म पर भोजन, दवाइयाँ, टैक्सी तथा अन्य घरेलू कार्यों की त्वरित सेवा चाहते हैं। इस माँग की पूर्ति के लिए विशाल और लचीले कार्यबल की आवश्यकता को गिग श्रमिक पूरा कर रहे हैं। बड़ी कम्पनियों के साथ-साथ स्टार्टअप्स के लिये भी गिग मॉडल अत्यन्त लाभप्रद है। उन्हें महँगे कार्यालयों के रखरखाव एवं स्थायी कर्मचारियों के दीर्घकालीन लाभों जैसे ग्रेच्युटी, पेंशन और कानूनी दायित्वों से मुक्ति मिल जाती है, जिससे लागत में कमी आती है।

गिग कार्यबल का वर्गीकरण:

तीव्र गति से बढ़ते गिग कार्यबल को विश्व स्तर पर एक नयी कार्यशैली की नींव रखने वाला माना जा रहा है। गिग कार्यों को उनकी कुशलता तथा प्रकृति के आधार पर दो श्रेणियों में विभक्त किया गया है। पहली श्रेणी में प्लेटफॉर्म-आधारित गिग कार्य आते हैं, जिनकी पूरी कार्य प्रणाली एक विशिष्ट ऐप पर आधारित होती है। इसमें फूड डिलीवरी पार्टनर, कैब ड्राइवर और ई-कॉमर्स डिलीवरी कर्मी शामिल हैं। इनकी आय का निर्धारण प्रति डिलीवरी या प्रति ट्रिप के आधार पर होता है। दूसरी श्रेणी में उच्च कुशलता युक्त स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले गिग कर्मी अथवा फ्रीलांसर शामिल हैं। इनमें सॉफ्टवेयर डेवलपर, ग्राफिक डिजाइनर, कॉपीराइटर और कंटेंट क्रिएटर जैसे पेशेवर आते हैं, जो Upwork और Fiverr पर कार्य करते हैं। गिग अर्थव्यवस्था इन पेशेवरों को लचीलापन, स्वतंत्रता और वैश्विक अवसर प्रदान करती है।

वैश्विक परिदृश्य :

गिग अर्थव्यवस्था अब एक वैश्विक परिघटना बन चुकी है। विश्व स्तर पर तेजी से बढ़ता हुआ गिग कार्यबल एक नयी आर्थिक क्रांति को बढ़ावा दे रहा है। McKinsey Global Institute के अनुसार अमेरिका में लगभग 15 से 20 प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या गिग कार्यों से जुड़ी हुई है। जबकि यूरोपीय संघ में डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगभग 2.4 करोड़ व्यक्ति गिग कार्य करते हैं। Uber और Lyft ने परिवहन क्षेत्र में क्रांति को जन्म दिया है। Airbnb ने आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्र में परिवर्तन की संभावनाएँ बढ़ायी हैं। Upwork और Fiverr ने वैश्विक स्वतंत्र बाजार को विस्तारित कर दिया है। Amazon Mechanical Turk ने सूक्ष्म कार्यों का संचालन संभव बनाया है। Task Rabbit घरेलू सेवाओं के डिजिटलीकरण का उदाहरण है।

भारतीय परिदृश्य :

भारत में गिग अर्थव्यवस्था का विस्तार तेजी से हो रहा है, जिससे रोजगार के स्वरूप में तेजी से परिवर्तन आया है। देश की विशाल युवा जनसंख्या, बढ़ती डिजिटल साक्षरता और स्मार्टफोन की सुलभता ने इस क्षेत्र को असाधारण रूप से प्रोत्साहित किया है। NASSCOM की रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक गिग अर्थव्यवस्था में 24 प्रतिशत योगदान करता है और विश्व के सबसे बड़े स्वतंत्र बाजारों में से एक है। प्रमुख भारतीय प्लेटफॉर्म में Swiggy और Zomato खाद्य वितरण क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। Ola और Uber कैब सेवाओं में क्रान्ति ला चुके हैं और 15 लाख से अधिक चालक इन सेवाओं हेतु पंजीकृत हैं। Urban Company घरेलू सेवाएँ प्रदान करने का सशक्त मंच है। Dunzo और Blinkit त्वरित वाणिज्य सेवाएँ प्रदान करते हैं। Toptal और Truelancer आई.टी. और पेशेवर सेवाएँ प्रदान करते हैं। नीति आयोग के अनुसार खुदरा और व्यापार क्षेत्र में 26.6 प्रतिशत गिग श्रमिक संलग्न हैं, परिवहन क्षेत्र में 22 प्रतिशत, निर्माण क्षेत्र में 20.8 प्रतिशत, मनोरंजन और मीडिया क्षेत्र में 12.3 प्रतिशत तथा अन्य क्षेत्रों में 18.3 प्रतिशत गिग कर्मी कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त कम्प्यूटर और आई.टी. क्षेत्रों में भी फ्रीलांस कार्य की बड़ी भूमिका है।

गिग अर्थव्यवस्था का प्रभाव :

गिग अर्थव्यवस्था ने आधुनिक श्रम बाजार, व्यवसाय और समाज पर गहरा प्रभाव डाला है। इस मॉडल ने उन लोगों को रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराये हैं, जो किसी कारणवश नियमित रोजगार नहीं कर सकते, जैसे गृहिणियाँ, वरिष्ठ नागरिक, विद्यार्थी एवं छात्र। डिजिटल प्लेटफॉर्म ने दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले प्रतिभावान व्यक्तियों को वैश्विक बाजार से जोड़कर क्षेत्रीय असमानता को कम करने में मदद की है। इस व्यवस्था में गिग कर्मी अपनी सुविधानुसार कार्य कर सकते हैं तथा एक से अधिक स्रोतों से आय अर्जित

Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-5(A)| May-2026

कर सकते हैं। वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में गिग श्रमिकों को निरन्तर अपने कौशल की उन्नति करने की प्रेरणा मिलती है, जिससे कुल उत्पादकता बढ़ती है। नियोक्ताओं के दृष्टिकोण से यह मॉडल उनकी लागत को कम करने में मदद करता है, क्योंकि इस व्यवस्था में उन्हें गिग कर्मियों को पेंशन तथा अन्य लाभ देने की आवश्यकता नहीं होती। इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार कर्मचारियों को नियुक्त कर सकते हैं तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद से दुनियाभर के स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले लोगों से काम ले सकते हैं। वर्तमान में लगभग 31 प्रतिशत गिग कर्मी कम कुशल कार्यों में तथा 22 प्रतिशत उच्च कुशल कार्यों में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। यद्यपि अभी तो भारत की जी.डी.पी. में इसका योगदान कम है, लेकिन नीति आयोग के अनुसार 2030 तक जी.डी.पी. में इसका योगदान 2 प्रतिशत से 3 प्रतिशत तक हो सकता है।

गिग अर्थव्यवस्था की चुनौतियाँ :

यद्यपि गिग अर्थव्यवस्था ने रोजगार के नवीन अवसर उपलब्ध कराये हैं, लेकिन इसके साथ संरचनात्मक तथा व्यावहारिक चुनौतियाँ भी जुड़ी हुई हैं। ये चुनौतियाँ मुख्य रूप से श्रमिकों, प्लेटफॉर्म कम्पनियों तथा सरकार के स्तर पर देखी जा सकती हैं। गिग कर्मियों के लिये निरन्तर कार्य की उपलब्धता निश्चित नहीं होती, जिसके कारण आय में स्थिरता नहीं रहती। प्लेटफॉर्म की चरण-दर-चरण प्रक्रिया, एल्गोरिद्म में परिवर्तन, बाजार की प्रतिस्पर्धा और आय की अनिश्चितता इनके कार्य-जीवन को प्रभावित करती है। कुछ अवधियों में कार्य के अभाव या रेटिंग में गिरावट से इनके पेशेवर भविष्य पर प्रभाव पड़ सकता है। किसी कम्पनी के नियमित कर्मचारी न होने के कारण गिग कर्मी स्वतंत्र कार्यकर्ता के रूप में वर्गीकृत रहते हैं, इसलिए वे अक्सर पी.एफ., पेंशन, ग्रेच्युटी, स्वास्थ्य बीमा तथा मातृत्व लाभ जैसे श्रम कानूनों की सुरक्षा से बाहर रह जाते हैं। बीमारी या आकस्मिक कार्य होने पर तत्कालीन सहायता का कोई प्रावधान नहीं होता। इस पर 'काम नहीं तो वेतन नहीं' का सिद्धान्त लागू होता है। अधिकांश प्लेटफॉर्म पर्याप्त बीमा सुविधाएँ नहीं देते, जिससे श्रमिकों को आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। अत्यधिक कार्य-दबाव, प्लेटफॉर्म-निर्धारित टार्गेट, बोनस प्रणाली और अपनी आय बनाये रखने की आवश्यकता के कारण अनेक गिग श्रमिक अधिक घंटे कार्य करते हैं, जो उनके स्वास्थ्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। इन श्रमिकों को कोई स्थायी सहकर्मी या कार्यस्थल नहीं होता, जिससे वे अकेलेपन और अलगाव का भी शिकार होते हैं। इस व्यवस्था में लैंगिक असमानताएँ भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। ILO की रिपोर्ट के अनुसार ऑनलाइन फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पर महिलाओं को समान कार्य के लिये पुरुषों की तुलना में कम दरें मिलती हैं। यह एक प्रकार का डिजिटल लिंग वेतन अन्तर परिलक्षित करता है।

वैश्विक नीतिगत प्रयास: श्रम संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा

यद्यपि गिग अर्थव्यवस्था वैश्विक अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है, लेकिन इसका नीतिगत ढाँचा अभी भी धीमी गति से विकसित हो रहा है। विभिन्न देशों ने अपने स्तर से कानून बनाये हैं, लेकिन एक समान वैश्विक नीति की कमी है। इन देशों ने गिग श्रमिकों की सुरक्षा के लिये अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाये हैं। ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय ने 2021 में Uber के चालकों को श्रमिकों का दर्जा देने के ऐतिहासिक फैसले सुनाया, जिससे उन्हें न्यूनतम वेतन तथा अवकाश का अधिकार मिला। कैलिफोर्निया में Proposition 22 पर हुई लम्बी कानूनी लड़ाई में स्वतंत्र ठेकेदारों और कर्मचारियों के बीच एक अलग श्रेणी बनाने की कोशिश की गयी। यूरोपीय संघ ने 2024 में Platform Work Directive पारित किया, जो प्लेटफॉर्म श्रमिकों के कार्य-व्यवहार, पारदर्शिता और अधिकारों के नियमन की व्यवस्था स्थापित करता है।

भारत में नीतिगत प्रयास:

भारत में 2020 में चार श्रम संहिताओं के माध्यम से श्रम कानूनों को सरल बनाने का प्रयास किया गया। इनमें सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में पहली बार गिग तथा प्लेटफॉर्म श्रमिकों को परिभाषित किया गया। इस कानून का उद्देश्य इन श्रमिकों को जीवन बीमा, विकलांगता बीमा, स्वास्थ्य लाभ और वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करना है। इसके लिये एक कल्याण कोष बनाने का प्रावधान किया गया है, जिसमें कम्पनियों को अपने कारोबार का 1.2 प्रतिशत तक योगदान देना होगा। यद्यपि इन संहिताओं का पूर्ण क्रियान्वयन अभी भी एक चुनौती बना हुआ है। राजस्थान गिग कर्मचारी (पंजीकरण और कल्याण) अधिनियम 2023 भारत का पहला राज्य स्तरीय कानून है, जो विशेष रूप से गिग श्रमिकों की सुरक्षा के लिये बनाया गया है। यह भारत का पहला ऐसा कानून है जो गिग श्रमिकों को एक कानूनी पहचान तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। इस कानून के अन्तर्गत एक कल्याण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान है, जो स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा और शिक्षा सहायता जैसी सुविधाएँ प्रदान करेगा। यह मॉडल अन्य राज्यों के लिये मार्गदर्शक का कार्य कर सकता है, क्योंकि यह कम्पनियों पर अतिरिक्त बोझ डाले बिना श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान करता है।

Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-5(A)| May-2026

प्रौद्योगिकी और भविष्य की संभावनाएँ:

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और स्वचालन गिग अर्थव्यवस्था के लिये दोधारी तलवार की तरह हैं। एक तरफ कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने नये प्रकार के गिग कार्य सृजित किये हैं, जैसे AI मॉडल प्रशिक्षण, आँकड़े तैयार करना, कंटेंट मॉडरेशन तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता परिणामों की समीक्षा। वहीं दूसरी तरफ स्वचालन कुछ दोहराये जाने वाले गिग कार्यों को प्रतिस्थापित कर सकता है। McKinsey के अनुसार 2030 तक कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा स्वचालन के कारण 37.5 करोड़ वैश्विक कार्यकर्ताओं को अपने पेशे बदलने होंगे। इससे अधिकतर लोग गिग कार्यों को अपनायेंगे, जिससे इस क्षेत्र में और अधिक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी में विकेन्द्रीकृत गिग प्लेटफॉर्म बनाने की क्षमता है, जहाँ मध्यस्थ कम्पनियों की भूमिका न्यूनतम हो और श्रमिकों को अपनी आय का अधिक हिस्सा मिले। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से भुगतान स्वचालित और पारदर्शी हो सकता है। आशा है भविष्य में नयी तकनीकें गिग अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनायेंगी।

निष्कर्ष :

निस्सन्देह गिग अर्थव्यवस्था आधुनिक श्रम बाजार का एक महत्वपूर्ण अंग बन चुकी है। यह लचीलापन, उद्यमशीलता और आर्थिक समावेशन के अनेक अवसर प्रदान करती है। भारत जैसे विकासशील देश में, जहाँ बड़ी संख्या में श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत हैं, गिग अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आवश्यकता इस बात की है कि हम इस व्यवस्था के लचीलेपन तथा श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करें। इस क्षेत्र में नवाचार तथा उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ श्रमिकों के बुनियादी अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिये एक संतुलित दृष्टिकोण को अपनाया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

सन्दर्भ सूची :

1. दत्त आर. तथा सुन्दरम के. पी. एम. (2020) भारतीय अर्थव्यवस्था, एस. चन्द पब्लिशिंग, नई दिल्ली
2. लाल एस. एन. तथा लाल एस. के., भारतीय अर्थव्यवस्था – सर्वेक्षण तथा विश्लेषण, शिवम पब्लिशर्स, इलाहाबाद
3. NITI Aayog (2022), India's Booming Gig and Platform Economy, Government of India
4. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (2023) वार्षिक रिपोर्ट, भारत सरकार
5. International Labour Organisation (2021), World Employment and Social Outlook 2021, Geneva
6. Chandrashekhar, R. (2025), Role of Gig Economy in Employment Generation: A Study. International Journal of Research in Management 7(1), 30–32
7. Mali, A.S. (2020), The Gig Economy: It's Impact and Implications on the Indian Economy, Sambodhi, 43(4), 72–77
8. https://kurukshetra.gov.in
9. https://yojana.gov.in